जनसत्ता

गहराती चुनौती

छत्तीसगढ़ के जंगलमहल और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली सहित देश के तमाम माओवादी हिंसा से प्रभावित इलाकों में किस तरह की चुनौतियां खड़ी हैं, यह सभी जानते हैं। यह भी तथ्य है कि इन इलाकों में समस्या से निपटने से लेकर सुरक्षा बलों की निगरानी में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जा रही है। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि इसके बावजूद माओवादियों पर पूरी तरह काबू पाना कैसे संभव नहीं हो पा रहा है। रविवार को सामने आई एक खबर के मुताबिक बस्तर में माओवादी हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित सुकमा जिले में कुछ समय पहले सीआरपीएफ के एक शिविर के ऊपर ड्रोन यानी मानवरहित यान मंडराता देखा गया। जैसे ही सीआरपीएफ के जवान सक्रिय हुए, वैसे ही वह गायब हो गया। यह इस बात का साफ संकेत है कि एक तो ड्रोन जैसे संवेदनशील साधन भी माओवादियों की पहुंच के दायरे में आ चुके हैं और दूसरे, वे उनके जरिए अपने प्रभाव वाले इलाकों में सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर निगरानी करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि अब तक इस उपकरण का उपयोग केवल सुरक्षा बल माओवादियों पर निगरानी के लिए करते रहे हैं। इस घटना के सामने आने के बाद सुरक्षा बलों को ड्रोन पर नजर पड़ते ही नष्ट करने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन इससे यह साफ है कि माओवाद प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की चुनौतियां बढ़ सकती हैं।

निश्चित तौर पर यह गहरी चिंता की बात है और इसके बाद यह पता लगाने की जरूरत है कि माओवादी समूहों तक ड्रोन जैसे संवेदनशील उपकरण कैसे पहुंचे और इसका जरिया कौन है। फिलहाल इस मामले में शुरुआती जांच के दौरान खुफिया एजेंसियों को मुंबई के एक दुकानदार पर शक है कि उसने अज्ञात लोगों को ड्रोन बेचे थे। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब माओवादियों के पास निगरानी रखने के लिए ड्रोन या दूसरे उपकरण होने के संकेत मिले हों। करीब साढ़े चार साल पहले खुद माओवादियों की एक चिट्ठी के जरिए हुए खुलासे के हवाले से यह खबर आई थी कि सुरक्षा बलों से मुकाबला करने के लिए वे ड्रोन और मोर्टार बनाना सीख रहे हैं। इसके अलावा, वे मोटरसाइकिल के इंजन को जोड़ कर ड्रोन और रिमोट के जरिए आइआइडी विस्फोट करने की तकनीक पर भी काम कर रहे हैं। यानी अब तक इस संदर्भ में जो ब्योरे उपलब्ध हो सके हैं, उससे यही संदेह है कि माओवादी समूहों की पहुंच या तो ड्रोन मुहैया कराने वालों तक है या फिर वे इसे तैयार करने की क्षमता विकसित कर चुके हैं।

जाहिर है, दोनों ही स्थितियों में यह सुरक्षा बलों और सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि माओवादी समूहों की आधुनिक तकनीकी तक पहुंच का सामने कैसे किया जाए। विडंबना यह है कि एक ओर माओवाद प्रभावित इलाकों में समस्या पर काबू पाने का दावा किया जा रहा है और दूसरी ओर माओवादियों की क्षमता में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। यह किसी से छिपा नहीं है कि आए दिन माओवाद प्रभावित इलाकों में तैनात सीआरपीएफ के शिविर या काफिलों पर घात लगा कर हमला किया जाता है और उसमें नाहक ही जवानों की जान चली जाती है। दरअसल, बस्तर या गढ़चिरौली जैसे उन क्षेत्रों की जटिल भौगोलिक संरचना माओवादियों को अपने अनुकूल लगती है और वहां कई बार वे किसी हमले को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि यह भी सच है कि सुरक्षा बलों ने भी अक्सर अभियान चला कर माओवादियों पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश की है। लेकिन ड्रोन से सीआरपीएफ शिविर की निगरानी के ताजा मामले से साफ है कि सुरक्षा बलों को अब अतिरिक्त चौकसी बरतने की जरूरत है।

बदलाव के संकेत

पड़ोसी देश श्रीलंका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में श्रीलंका फ्रीडम पार्टी (एसएफपी) के उम्मीदवार गोटबाया राजपक्षे की जीत ने एक बार फिर से देश की राजनीति की दिशा बदल दी है। राजपक्षे ने यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) के उम्मीदवार सजित प्रेमदासा को तेरह लाख वोटों से हराते हुए यह साबित कर दिया है कि उनकी पार्टी एसएफपी और राजपक्षे परिवार का दबदबा अभी भी पहले की तरह ही कायम है। श्रीलंका में 2005 से 2015 तक एसएफपी सत्ता में रही थी और तब गोटबाया के बड़े भाई महिंदा राजपक्षे देश के राष्ट्रपति रहे थे और उनके शासनकाल में गोटबाया दो साल रक्षा मंत्री भी रहे थे। इस चुनाव में एसएफपी की जीत इसलिए भी महत्त्वपूर्ण मानी जा रही है कि श्रीलंका के सिंहल बहुल दक्षिणी हिस्से में राजपक्षे की पार्टी फिर से ताकतवर बन कर उभरी है। हालांकि देश के मुसलिम और तमिल बहुल इलाकों में श्रीलंका फ्रीडम पार्टी को खासी हार का सामना करना पड़ा। इससे यह भी साफ है कि देश में लंबे समय से तमिल समुदाय व अल्पसंख्यकों और सिंहलियों के बीच जो वैमनस्य चला आ रहा है, उसकी खाई अभी तक पटी नहीं है।

यह तो ठीक है कि महिंदा राजपक्षे के भाई के नाते श्रीलंका की राजनीति में गोटबाया का दबदबा बढ़ता गया, लेकिन इससे भी ज्यादा उन्हें जिस बात के लिए जाना जाता है वह है देश से मुक्ति चीतों का सफाया। राजपक्षे मूल रूप से फौजी अफसर रहे हैं और तमिल इलाकों से लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एलटीटीई) के सफाए के अभियान को उन्होंने अंजाम तक पहुंचाया। इसलिए वे श्रीलका में 'टर्मिनेटर' के नाम से भी विख्यात हैं। सिंहली बौद्ध समुदाय में वे महानायक के रूप में देखे जाते हैं तो तमिल समुदाय में उन्हें आज भी खलनायक के तौर पर ही देखा जाता है। यही वजह है कि तमिल बहुल इलाकों में श्रीलंका फ्रीडम पार्टी जीत का मुंह नहीं देख पाई। सवाल है कि क्या नई सरकार का तमिलों के प्रति पहले जैसा द्वेषपूर्ण रवैया रहेगा या फिर वक्त के साथ उसमें कुछ उदारता देखने को मिलेगी। श्रीलंका में सिंहलियों और मुसलमानों के बीच होते रहने वाले संघर्ष भी देश के लिए कम बड़ी चुनौती नहीं हैं। श्रीलंका में पिछले साल चर्च पर जिस तरह से आत्मघाती हमले हुए और इसके पीछे इस्लामी आतंकवाद का हाथ माना गया, उससे भी नई सरकार को निपटना है। सिंहलियों को लगता है कि गोटबाया राजपक्षे ने जिस तरह से एलटीटीई का सफाया किया, उसी तरह वे इस्लामी आतंकवाद से भी निपट पाने में सक्षम होंगे।

श्रीलंका का एकमात्र पड़ोसी देश भारत है। इसलिए गोटबाया का सत्ता में आना भारत के लिए हर तरह से महत्त्वपूर्ण है और इसके दूरगामी अर्थ भी हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि श्रीलंका में एक बार फिर से चीन समर्थक सत्ता की वापसी हुई है। महिंदा राजपक्षे ने भी अपने दस साल के शासन में चीन के साथ गहरी दोस्ती निभाई थी और हंबनटोटा बंदरगाह का निर्माण कर हिंद महासागर में चीन की सैन्य गतिविधियों के लिए स्थायी रास्ता बना दिया था। अब भारत के दो पड़ोसी नेपाल और श्रीलंका में चीन समर्थक सरकारें हो गई हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का चीन के प्रति प्रेम जगजाहिर है। फिर, भारत श्रीलंका में रह रहे तमिलों के हितों की अनदेखी नहीं कर सकता। यही वजह है कि श्रीलंका की नीतियां सुरक्षा और सामरिक कारणों के अलावा भारत की अंदरूनी राजनीति को प्रभावित करती हैं। ऐसे में श्रीलंका की नई सरकार भारत के प्रति क्या रुख रखती है, यह आने वाला वक्त बताएगा।

कल्पमेधा

अपने अज्ञान का आभास होना ही ज्ञान की तरफ बड़ा कदम है।
-डिजरायली

मूल्यपरक शिक्षा और सतत विकास लक्ष्य

रमेश पोखरियाल 'निशंक'

मुझे लगता है कि हमें अपने छात्रों को यह सिखाना होगा कि स्थिरता केवल पर्यावरण के बारे में ही नहीं है, बल्कि हमें समग्र विकास के विषय में सोचना है। एक समाज के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में हमारे कार्यों से प्रकृति के साथ सामंजस्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस बारे में प्रश्न का उत्तर ढूंढ़ना है।

सदियों पुरानी भारतीय संस्कृति ने संपूर्ण विश्व को परिवार माना है। 'अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम।' संपूर्ण दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम का महान विचार लेकर भारत देश ने 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः' की परिकल्पना को स्वीकार करते हुए संपूर्ण मानवता के कल्याण की प्रार्थना की है। हमारा चिंतन, हमारे दर्शन और हमारे मूल्यों में एक ही भावना परिलक्षित होती है कि संसार में कोई कष्ट में न रहे। एकात्म मानववाद का चिंतन कर हमने समाज में अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प लिया है। पिछड़े, दलित, उपेक्षित वर्ग तक पहुंचना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

विश्व बंधुत्व, सामाजिक समरसता, सौहार्द, परोपकार, सहिष्णुता, प्रेम की भावना को हम शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाने और पुष्पित पल्लवित करने में सक्षम हैं। शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे हम समग्र विकास की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। विश्व में शीर्ष पर रहने का श्रेय हमें शिक्षा के माध्यम से ही मिला। विश्व गुरु भारत पुरातन काल में ज्ञान और विज्ञान का नेतृत्व केवल इसलिए कर पाया क्योंकि उसकी शिक्षा सर्वोत्कृष्ट और मूल्यों पर आधारित थी। नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी विश्वविद्यालय दुनिया भर के छात्रों और विद्वानों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। सदैव से ही भारत अपनी मूल्यपरक शिक्षा द्वारा वैश्विक कल्याण के साझा उद्देश्यों को साकार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ एक सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाता रहा है। आज के चुनौतीपूर्ण वातावरण में भारत विश्व का तीसरा बड़ा शिक्षा तंत्र होने के नाते तैंतीस करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य निर्माण के लिए कृत संकल्पित है। देश में एक हजार से ज्यादा विश्वविद्यालय और पैंतालीस हजार से ज्यादा डिग्री कालेज हैं।

सतत विकास के तीन स्तंभ आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण स्थिरता और विकास संतुलित करने पर केंद्रित है। मुझे लगता है कि हमें अपने छात्रों को यह सिखाना होगा कि स्थिरता केवल पर्यावरण के बारे में ही नहीं है, बल्कि हमें समग्र विकास के विषय में सोचना है। एक समाज के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में हमारे कार्यों से प्रकृति के साथ सामंजस्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस बारे में प्रश्न का उत्तर ढूंढ़ना है। 'स्थिरता' की परिभाषा से अपने विद्यार्थियों को अवगत कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यही कारण था कि जहां हमने अपने परिसरों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है, वहीं 'एक पेड़ एक छात्र' अभियान चला कर अपने परिसरों को हरित परिसर बनाने का प्रयास किया है। हम शिक्षा, विज्ञान, पर्यावरण और संस्कृति के क्षेत्र में अंतराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति के निर्माण के अपने मूल जनादेश को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं। मुझे लगता है कि युगों-युगों से चली आ रही हमारी शिक्षा पद्धति हमारा दर्शन, हमारा चिंतन और हमारा भाव- सब कुछ मानवता के कल्याण के लिए केंद्रित रहता है। 'असतो मा सदगमयः' असत्य से सत्य की ओर एवं 'तमसो मा ज्योर्तिगमयः' अंधकार से प्रकाश की ओर प्राणी मात्र को ले जाने के लिए हम संकल्पित हैं।

हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक बच्चे और नागरिक को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। हम समग्र शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को लागू कर समस्त भारत में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। तैंतीस वर्षों के अंतराल में हम देश के शैक्षिक क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने वाली नई शिक्षा नीति लाने के लिए कृत संकल्पित हैं। हमारी नई शिक्षा नीति गुणवत्तापरक, रोजगारपरक है, नवचारयुक्त, कौशलयुक्त है, सामाजिक सरोकारों से युक्त है, व्यावहारिक और शोधपरक है और पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाली है।

भारत विश्व के सबसे बड़े सार्वजनिक लोकतांत्रिक परामर्श अभियान से नई शिक्षा नीति को कार्य रूप देने की ओर गतिशील है। लगभग सवा दो लाख लोगों के सुझाव इस बात का परिचायक हैं कि हमने शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए सभी हितधारकों तक पहुंचने का प्रयास किया है। विद्यार्थी, अध्यापक, विद्यालय प्रबंधन, प्रशासक, नीति निर्माता, जनप्रतिनिधि एवं गैर सरकारी संगठनों समेत हमने हर वर्ग तक पहुंचने में सफलता पाई है। सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में यह नीति सफल साबित होगी। हमारा लक्ष्य है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर शिक्षा को नवाचार युक्त गुणवत्तापरक बनाया जाए। भारत उच्च शिक्षा नीति को गुणात्मक एवं वहनीय बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

स्वयं पोर्टल के माध्यम से हम भारत के ही नहीं, बल्कि विदेशी छात्रों को भी निशुल्क उच्च शिक्षा देने के लिए प्रयासरत हैं। भारत के ही एक करोड़ तेईस लाख छात्र स्वयं पोर्टल के तहत शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। विज्ञान भारती एवं 'आरोग्य भारती' के माध्यम से हम ज्ञान के भंडार को निशुल्क बांटने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ हमारा इस संबंध में समझौता हो चुका है। समूचे विश्व के छात्र भारत में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 'स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम' के तहत भारत की सौ से ज्यादा सर्वोत्तम शिक्षण संस्थाएं विश्व भर में छात्रों के लिए आकर्षक शिक्षा केंद्र के रूप में उपलब्ध हैं।

शिक्षा के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को जागरूक करना हमारी प्राथमिकता है। भाषा राष्ट्र की अभिव्यक्ति है और भाषा के बगैर राष्ट्र गूंगा है। भाषा के महत्त्व को समझते हुए नई नीति के माध्यम से हम देश की हिंदी, संस्कृत सहित सभी भारतीय भाषाओं को संरक्षित, पुष्पित एवं पल्लवित करने में जुटे हैं। भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद से संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध है। मानव सभ्यता हमारी आधुनिक जीवन शैली को बनाए रखने के लिए संसाधनों का उपयोग करती है। मानव इतिहास में अनगिनत उदाहरण हैं जहां सभ्यता ने विकास के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। हमें क्षति और विनाश से बचाते हुए इस बात को ध्यान में रखना है कि हम प्राकृतिक दुनिया के साथ कैसे तालमेल बिठा सकते हैं।

ब्रिटिश काल के दौरान शुरू हुई मूल्यों की गिरावट लंबे समय तक जारी रही। यह हमारा सौभाग्य रहा कि स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे सिद्धांतों और मूल्य युक्त नेतृत्व ने हमारा मार्गदर्शन किया। उन्होंने सत्य और अहिंसा के अपने शक्तिशाली मूल्यों के साथ भारत को अपनी ताकत वापस पाने में मदद की। आजादी के सत्तर वर्षों के बाद प्रभावी प्रबंधन और अस्तित्व के लिए इन मूल्यों पर वापस जाने की आवश्यकता है।

मानवता के लिए शिक्षा को संयुक्त रूप से बदलने के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारी की अनूठी पहल को साकार करने के लिए एवं मानवता के लिए शिक्षा को संयुक्त रूप से बदलने के लिए मैं वैश्विक साझेदारी की आशा करता हूं। आज हम परिवार के अंदर बंट गए हैं, खुद को कंप्यूटर तक सीमित कर लिया है और स्मार्टफोन को अपनी दुनिया बना लिया है। इन जंजीरों से निकलने में बापू के विचार हमारे लिए मददगार साबित हो सकते हैं।

आज के युग में भारत इस तरह की पहल शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, जल और स्वच्छता के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ मिल कर करना चाहता है। मैं सभी सम्मानित देशों से अनुरोध करता हूं कि हम सब मिल कर के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करें।

(लेखक मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। यह लेख यूनेस्को में दिए उनके भाषण का अंश है।)

नशे के उत्सव

संतोष उत्सुक

धार्मिक आयोजनों की आन-बान-शान में पिछले सालों में काफी इजाफा हुआ है। मेरे घर की छत से जुलूस की रौनक खूब दिखती है। मैंने देखा है कि जुलूस का मुख्य आधार और आकर्षण, अनगिनत लाउडस्पीकरों पर डीजे की तीव्र और अधिकतम फिल्मी धुन आधारित भजनों पर सैकड़ों युवा डांस करते हैं। विद्यार्थी अपने दोस्तों के साथ मजे के लिए आते हैं, जिनमें युवतियां भी शामिल होती हैं। जुलूस शाम को होता है, संभव है कि ऊर्जा बढ़ाने के लिए एकाध पैग शराब भी ले ली हो। वैवाहिक या उत्सवीय मनोरंजन के लिए यह सामान्य बात है। उत्सव से अगले दिन की चित्र-खबरें बताती हैं कि भक्त, जिनमें राजनीतिक खिलाड़ी और अनाड़ी शामिल हैं, की संस्थाओं द्वारा आयोजित अनेक कार्यक्रमों में शोरदार डीजे का प्रबंध हुआ। भांग के पकौड़े और घोटा, अगाध प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के साथ लेने के लिए युवा बाजुओं में होड़ रही। चिलम से कश लगाने के शौकीनों के लिए चांदी से बनी चिलमों का प्रबंध भी किया। देवताओं की शादी के जश्न में प्रसाद ग्रहण करना, बताते हैं एक हजार गुणा फल देता है!

खीर या फलों का प्रसाद पेट भरता है, लेकिन दूसरा प्रसाद चित्त प्रसन्न कर देता है और प्रिय साथी का संग हो तो बेहद आनंद मिलता है। पेट संतुष्टि से ज्यादा मन संतुष्टि मानी जाती है। साफ है कि इन आयोजनों में नशे को मनोरंजन के बहाने एक 'लांच पैड' मिल जाता है। धार्मिक आयोजनों की तड़क-भड़क, डीजे का करारा छौंक, भांग और घोटे की सुलभ उपलब्धता युवा जीवन को अनुशासन तोड़ने के लिए उकसाती है। क्या प्रसाद के नाम पर भांग, घोटा या ऐसा कुछ और नशे का खुला प्रचार नहीं है? यह विडंबना है कि एक तरफ तो सरकार और संस्थाएं मिल कर भांग के पौधे उखाड़ने का अभियान चलाती हैं, लेकिन हर बरस फिर हरी-भरी हो जाने वाली भांग ही अभियान को उखाड़ देती है। प्रसाद रूप में सर्वत्र उपलब्ध होकर, राजनेताओं के प्रश्रय में बंट कर फिर अपने बाहुपाश में बांधती है। यहीं विद्यार्थी जीवन में अनुशासन से छिटक कर जिंदगी, नशे के मनोरंजन की गर्त में धंसती जाती है।

दुनिया मेरे आगे

हजारों युवाओं में जो मस्ती और मनोरंजन के लिए जुलूस में शामिल होते हैं, कहीं न कहीं नशे का बीज रोपित हो जाता है जो बड़ा होते-होते पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और विशेषकर दिशाहीन शिक्षा और बेरोजगारी जैसी परिस्थितियों के कारण दूसरे नशों की खाद से बढ़ता है। नशा बेचने वालों का तंत्र बहुत चतुर है। पुलिस सूचनाओं और खुफिया सूचनाओं के आधार पर अपने हिसाब से निरंतर काम करती है। लेकिन अधिकतर सूचनाएं लुप्त रह जाती हैं। कभी पुलिस छापे में 1.18 ग्राम स्मैक मिलती है तो कभी एक किलो चरस या काफी मात्रा में चिट्टा। सरकार अनेक योजनाओं के अंतर्गत प्रयास करती है। स्कूल और सामाजिक संस्थाएं भी सेमिनार, जुलूस के माध्यम से कोशिश करते हैं, लेकिन नशे की लत निरंतर लगाए रखने वाले भी कम नहीं होते।

किसी जमाने में नशा करने वाले कफ सिरप गटकते थे, ब्रैड पर आयोडेक्स लगाकर खाते थे। अब तो तंबाकू, चरस, अफीम, गांजा, भुक्की, सुल्फा- कितना कुछ कितनी जगह आसानी से उपलब्ध है! दवा दुकानों पर नशीली गोलियां भी बेची जा रही हैं, आम जनता और महिला मंडल संघर्षरत हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। नियम और कानून सख्त हैं, प्रशासन है, लेकिन कार्यान्वयन की संजीदगी गायब है।

पहले जीवन सादा, सरल था और युवा मेहनती। लेकिन विकास और संप्रेषण के अति विकसित होते साधनों ने नशे पर भी बहुत काम किया और जाल बिछाने में समय नष्ट नहीं हुआ। कहा जाता है कि युवा अपना समय पढ़ाई और खेल में लगाएं, नशे में नहीं। लेकिन हर हाथ में मोबाइल की उपलब्धता ने हर समय अपने आप से खेलने की जो सुविधा दी है, वह अब दुविधा में तब्दील हो चुकी है। नशा तेजी से युवावस्था से बचपन की ओर बढ़ रहा है जो ज्यादा खतरनाक प्रवृत्ति है। जरूरत है बेहद व्यावहारिक तरीके अपनाने की, बचपन से युवा हो रहे युवक-युवतियों को घर पर उनके अभिभावकों स्कूल में अध्यापकों और वरिष्ठ मित्रों द्वारा नशे के दूरगामी प्रभावों के बारे में खबरदार करना बेहद आवश्यक है। सामाजिक संस्थाओं की भूमिका कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। बच्चा अपने अभिभावकों की व्यस्तता के कारण वांछित समय और तवज्जो न मिलने के कारण भी नशे की राह पकड़ता है। बच्चों और विद्यार्थियों को अभिभावकों और अध्यापकों की डांट और सजा का खौफ अनुशासन में रखता था, लेकिन हम सबने मिल कर सामाजिक ढांचे का पुनर्निर्माण ऐसा किया कि स्वतंत्रता ज्यादा बेलगाम हो गई। अब अभिभावकों और अध्यापकों की निरंतर और संयुक्त देखरेख और जिम्मेदारी की जरूरत है। सरकार की ओर से पुलिसकर्मियों और दवा निरीक्षकों की संख्या बढ़ा कर नशे के फैलते जाल को खत्म करने के लिए अतिरिक्त सुविधाएं देना बहुत लाजिमी है। हमें फिर पुराने तौर-तरीकों की तरफ लौटने की जरूरत है।

विमर्श की जरूरत

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, उत्तराखंड आयुर्वेद संस्थान, राजस्थान विश्वविद्यालय सहित देश के अनेक शिक्षण संस्थानों में इन दिनों विद्यार्थी पढ़ाई के स्थान पर प्रदर्शनरत हैं। सरकारी नीतियों, मनमानी, बढ़ती फीस आदि कारणों से विद्यार्थियों में असंतोष उपजा है जिसके चलते वे सरकारी शिक्षण संस्थानों में बढ़ते व्यापारीकरण, निजीकरण और स्वयं वित्तपोषित पढ़ाई का एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं।

भारतीय संविधान कल्याणकारी राज्य की संकल्पना करता है। इसका अर्थ है कि नागरिकों को शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना राज्य का दायित्व है। देश के हर व्यक्ति तक जीवन की ये मौलिक सुविधाएं न पहुंचा पाना राज्य की नाकामी है। ऐसे में यदि सरकार शिक्षा में भी धंधा करने लग जाए, फायदा-मुनाफा देखकर शिक्षण संस्थान चलाएं तो यह खेदजनक है।

उत्तराखंड के सोलह आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के हजारों छात्र-छात्राएं बीते डेढ़ महीनों से नियम-कायदों व नैतिकता को ताक पर रख कर प्रशासन द्वारा की गई फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। धरना-प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठियां झेल रहे हैं। संवैधानिक तरीके से उच्च न्यायालय में मामला जीतने के बाद भी बढ़ी हुई फीस वापस नहीं हो रही है। इसी तरह दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र अपने उत्तर परिसर स्थित रक्षा मंत्रालय की जमीन को एक निजी बिल्डर को दिए जाने और उस पर 39 मंजिला इमारत बनने के विरोध में हड़ताल पर है। विद्यार्थियों और शिक्षकों का कहना है कि विश्वविद्यालय परिसर में कोई भी निर्माण शुरू करने से पहले विश्वविद्यालय से स्वीकृति लेना जरूरी है, लेकिन बगैर किसी अनुमति के निजी कंपनी यहां निर्माण कर कानून का उल्लंघन कर रही है। चूंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के पांच फीसद विद्यार्थियों के लिए ही हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है तो छात्र चाहते हैं कि इस जमीन पर हॉस्टल बनना चाहिए।

राजस्थान विश्वविद्यालय में साल-दर-साल परीक्षा फीस में बढ़ोतरी की जा रही है। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन फीस घटाने की कवायद नहीं कर रहा। ऐसे में देश के सरकारी विश्वविद्यालों में शिक्षा के इस कदर होते व्यापारीकरण से आर्थिक तौर पर कमजोर विद्यार्थियों को बेहतर संस्थान में पढ़ने व उच्च शिक्षा प्राप्ति से वंचित होना पड़ सकता है। वह भी तब जब दुनिया के शीर्ष 300 शिक्षण संस्थानों में एक भी भारतीय विश्वविद्यालय शामिल नहीं। हमारे केवल 2.5 प्रतिशत कॉलेज पीएचडी करा पाने में सक्षम हैं। इसी के साथ केवल 0.5 फीसद छात्र शोध शिक्षा हासिल कर पाते हैं। हमारे उच्च शिक्षण संस्थान वैज्ञानिक सोच और शोध विकसित कर पाने में समर्थ नहीं हैं। यही कारण है कि आज देश में उच्च शिक्षा की सुलभता व सुगमता अति आवश्यक है। हर आम व वंचित छात्र से दूर जाती उच्च शिक्षा को बचाना जरूरी है। सस्ती शिक्षा के लिए छात्र-छात्राओं द्वारा किया जा रहा विरोध प्रदर्शन राजनीतिक प्रभुत्व की इच्छाशक्ति के लिए न होकर विश्वविद्यालयी शिक्षा को बचाए रखने के लिए है। अपनी मांगों व विषयों पर अक्सर प्रदर्शन कर विरोध जताने वाले विद्यार्थियों को प्रशासन से तार्किक विमर्श का मौका देना चाहिए।

● *कृष्ण जांगिड़, राजस्थान विश्वविद्यालय*

सच के साथ

कुछ दिन पहले पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक ने टीवी की बहसों या 'टॉक शो' के दौरान उद्घोषकों के विशेषज्ञ के रूप में राय देने पर प्रतिबंध लगा दिया। यह अच्छा कदम है। इन दिनों वैश्विक स्तर पर, विशेष रूप से भारत में, देखा जा रहा है कि मीडिया किसी भी मुद्दे पर स्वयं एक निर्णयदाता की शब्दावली का प्रयोग करते हुए तथ्यों को परोसने लगता है। वह खुद ही विशेषज्ञ बन जाता है। आज की भाग-दौड़ वाली जिंदगी में लोग खबरों की सत्यता तक पहुंचने की जहमत नहीं उठाना चाहते। जो टीवी पर देखा वही मान लिया। यहां तक तो गनीमत है। दिक्कत तब खड़ी हो जाती है जब हम 'तथाकथित सत्य' को 'ध्रुव सत्य' मानकर प्रतिक्रिया देने लगते हैं। इससे जो पूर्वाग्रह निर्मित होता है वह हमारी एकता में बाधक है।

● *विशाल कुमार शर्मा, जेएनयू, दिल्ली*

विविधता का संरक्षण

बदलते वैश्विक परिवेश और जलवायु में होते परिवर्तन को देखते हुए मानव अस्तित्व के लिए जैव विविधता अति आवश्यक है। जीवन का हर रूप एक-दूसरे पर इतना निर्भर है कि किसी एक प्रजाति पर संकट आने से दूसरे में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। यदि पौधों और प्राणियों की प्रजातियां संकट की स्थिति में होती हैं तो इससे पर्यावरण में गिरावट उत्पन्न होती है और अंततः मनुष्य का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है।

लिहाजा, आज यह अति अनिवार्य है कि मानव को पर्यावरण-मैत्री संबंधी पद्धतियों के प्रति जागरूक किया जाए और विकास की ऐसी व्यावहारिक गतिविधियां अपनाई जाएं जो दूसरे जीवों के साथ समन्वित और सतत पोषणीय हों। इस तथ्य के प्रति भी जागरूकता बढ़ रही है कि संरक्षण तभी संभव है और दीर्घकालिक होगा, जब स्थानीय समुदायों व प्रत्येक व्यक्ति की इसमें भागीदारी होगी। इसके लिए स्थानीय स्तर पर संस्थागत संरचनाओं का विकास आवश्यक है। केवल प्रजातियों का संरक्षण और आवास स्थान की सुरक्षा अहम समस्या नहीं है बल्कि संरक्षण की प्रक्रिया को जारी रखना भी उतना ही जरूरी है।

● *सूर्यभानु बांधे, रायपुर, छत्तीसगढ़*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

सांस में जहर

तरक्की की दौड़ में हम इतने बेखबर हुए कि दिल्ली की फिजाओं में जहर घुल गया और हम खड़े-खड़े गुबार देखते रहे। मौसम के बहकावे में तलवे की धूल भी सिर के ऊपर उड़ने लगी। हंगामा खूब बरपा मगर सांस में घुलते जहर से राहत की तरकीब नहीं मिली। दिल्ली के धुएं का असली गुनहगार पराली है या नहीं मगर राजनीतिक आबोहवा में बेशक बवंडर मच गया। शहर की जानलेवा हवा पर बैठक में पच्चीस सदस्यों की अनुपस्थिति और गौतम गंभीर की जलेबी सुर्खियां बन कर रह गईं। बहरहाल, नई फसल की तैयारी के मद्देनजर महंगी मजदूरी का मारा किसान खेतों में पराली जलाने पर मजबूर है। पराली का इस्तेमाल कागज उत्पादों के लिए सुनिश्चित करना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। लिहाजा, सरकार को पराली हटाने की जिम्मेदारी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत कागज निर्माताओं को सौंप देनी चाहिए। राजनीति की भयावह आग दिल्ली की हवा को और जहरीला न बना दे, पराली सहित सभी विकल्पों पर गंभीरता दिखानी होगी।

● *एमके मिश्रा, रातू, झारखंड*